शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

भारत-पाक सम्बन्ध: स्वरूप और बदलाव
(1990 से 2005 के संदर्भों में)

डॉ.शीला ओझा
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय,
नागदा, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत-पाक सम्बन्ध 1947 के पश्चात् ही तनाव और आपसी सद्भाव को विकसित करने की प्रक्रिया में ही विकसित हुए। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 1990-91 के पश्चात् दोनों देशों में जहाँ परस्पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल रहा वहीं 1998 के बाद अणु शक्ति का दर्जा प्राप्त करने से दोनों देशों में नये तनाव देखे जा सकते हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि वर्ष 2000 के बाद दोनों देशों में सहयोग के नये प्रयास हुए हैं जो अन्तरराष्ट्रीय तनाव और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य करने की प्रक्रिया का परिणाम ही है। प्रस्तुत शोध पत्र में विगतकाल में भारत-पाक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। इस विवेचन से भविष्य का आकलन करने में संबंध पुनर्निर्धारण में सहायता मिलेगी।

प्रस्तावना

भारत-पाक सम्बन्धों का विश्लेषण भारत की विदेश नीति का सबसे जटिल पक्ष है। यों ये संबंध लगातार कई परेशानियों से ग्रस्त रहे हैं और इन संबंधों में जनमत की संवेदनशीलता सबसे अधिक रही है जिसके फलस्वरूप ये संबंध और भी अधिक जटिल हुए हैं। दोनों देशों के बीच तीन बार क्रमशः 1948, 1965 और 1971 में सशस्त्र संघर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में जबकि दोनों राष्ट्र अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं तब पारस्परिक तनाव का स्वरूप और उसके प्रभावों में बदलाव आ गया है। वैसे यह विशेष उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के पश्चात् सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ है। पिछले 27 वर्षों में अनेक अवसर ऐसे आये हैं जबकि दोनों राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष के अवसर आ सकते थे किन्तु दोनों देशों की राजनयिक सक्षमताओं और युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों की संभावनाओं के फलस्वरूप सशस्त्रसंघर्ष के अवसर लगातार टलते आ रहे हैं। भारत-पाक संबंधों में तनावों के कारणों की खोज अनुचित नहीं है। इन कारणों में सर्वप्रथम दोनों देशों के बीच विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वास्तविकता यह है कि 1947 में भारत-पाक विभाजन से ही दोनों देशों के बीच तनाव को जन्म दिया है। विभाजन यदि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के साथ होता तो अच्छे संबंधों की स्थापना होती लेकिन इसके विपरीत भारत-पाक विभाजन आपसी अविश्वास, संदेह, कटुता और वैमनस्य पर हुआ है, इसलिए दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव का जन्म आरम्भ

से ही हुआ है। भारत-पाक के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुए उनमें कुछ प्रमुख, जैसे- अन्तरराष्ट्रीय सीमा-विवाद, अल्पसंख्यकों की समस्या, देशी राजा और नवाबों की रियासतों के विलय का प्रश्न एवं सैन्य सामग्री का बंटवारा है। इन समस्याओं में से कुछ का निदान हो गया लेकिन रियासतों के विलय से संबंधित विवाद सबसे मुश्किल था। इसी कारण विभाजन के बाद तुरन्त जम्मू-कश्मीर रियासत के विलय के मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1948 में हुआ। वैसे भारत-पाकिस्तान के बीच आपसी नाराजगी के कारणों का विश्लेषण करते समय एक विचार यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नाराजगी मूल आस्थाओं के कारण रही है। भारत-पाकिस्तान के बीच विभाजन का मूल आधार द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त है जिसमें धार्मिक आधारों पर भारत-पाकिस्तान के विभाजन की मांग थी और 1947 में दोनों राष्ट्रों के बीच इस आधार पर विभाजन हुआ और इसे तब और भी अधिक सुदृढ़ किया गया जबकि पाकिस्तान ने अपने आपको इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित किया और भारत ने अपने को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। हाल ही में पाकिस्तान की सीमा में इस्लाम के आधार पर अपने नियमों का निर्माण कर एक बार फिर पाकिस्तानी राजनीति को पीछे धकेलने की चेष्टा की है। ये प्रयास इस मूल भावना को दृढ़ करते हैं कि भारत और पाकिस्तान की स्थापना दो अलग-अलग मूल्यों की स्थापना को लेकर हुई और यह अविश्वास और तनाव का मूल कारण है।

भारत-पाक संबंधों के कारणों में पाकिस्तान के मनोविज्ञान का उल्लेख मणिशंकर अय्यर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तानी पेपर्स में किया है। उनके अनुसार पाकिस्तान का पड़ोसी भारत, पाकिस्तान की तुलना में राजनैतिक रूप से अधिक प्रबुद्ध है, प्रजातांत्रिक परम्पराओं की जड़े अधिक गहरी हैं और नागरिक जीवन अधिक सम्पन्न और सुविधाओं से भरपूर है। इसीलिए पाकिस्तानी नेतृत्व के लिए यह ईर्ष्या का विषय रहा है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए मणिशंकर स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान में नाराजगी का एक कारण यह भी होता है कि यह तथ्य या यह जानकारी भारत से जुड़ी हुई और भारत पर आधारित है।

भारत-पाक संबंधों के एक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को रेखांकित करते हुए मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पाकिस्तान के मनोविज्ञान में यह तथ्य बहुत स्पष्ट तौर पर घर कर गया कि वह एक छोटा देश है। वैसे जनसंख्या इण्डोनेशिया के बराबर है परन्तु उसमें यह भाव लगातार बना हुआ है कि वह एक छोटा देश है और उसे अपने अस्तित्व के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ता है और भारत उसके अस्तित्व के लिए लगातार खतरा है। इस दृष्टि से वे सब प्रयास जो भारत-पाक संबंधों में एकता और निकटता के लिए होते हैं, वे पाकिस्तान में एक मनोवैज्ञानिक भय को जन्म देते हैं और अपने अस्तित्व के लिए पाकिस्तान को और अधिक उग्र नीतियों के लिए बाध्य करते हैं।

भारत-पाक संबंधों के विश्लेषक जिनमें जे.एन.दीक्षित का नाम प्रमुख है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि दोनों देशों के अभिजन जिनमें पाकिस्तानी सैन्य अभिजन विशेष रूप से सक्रिय हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में तनावों के बने रहने के निरन्तर

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

अवसर होने चाहिए, क्योंकि जब तक भारत-पाक तनाव बने नहीं रहेंगे, तब तक पाकिस्तान में सैन्य अभिजन महत्त्वपूर्ण नहीं होगा। भारत-पाक तनाव सैन्य अभिजन को एक विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं।

1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका को पाकिस्तान का सैन्य अभिजन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। भारत में इस विभाजन को उस विचारधारा की विजय माना जाता है जिसके अन्तर्गत धर्म पर आधारित राज्य निर्माण अनुचित है और सांस्कृतिक तथा भाषायी एकीकरण के अभाव में राष्ट्र का संचालन और स्थायित्व संभव नहीं है। नये पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर रही है और उसके फलस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिकारों ने भारत की पश्चिमी सीमाओं को निरन्तर तनावपूर्ण बनाये रखने का कार्य किया है। इसके अन्तर्गत पंजाब एवं कश्मीर में आतंकवाद और छोटे स्तर पर अनुपस्थित युद्ध लगातार चल रहा है, जिसके फलस्वरूप भारत-पाक सीमाएं लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। अनुपस्थित युद्ध के कारण अस्थिरता के साथ-साथ क्षेत्र में लम्बे समय तक तनाव की उपस्थिति भी रहती है। पिछले 15 वर्षों से यह प्रवृत्ति भारत-पाक संबंधों को लगातार प्रभावित कर रही है।

भारत-पाक संबंधों का विश्लेषण एक और दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है जिसमें दोनों देशों की सैन्य तैयारी और व्यय का आधार है। भारत की रक्षा सेनाएं 1.050 हजार 1996-97 तथा 1997-98 में 320,000 करोड़ रुपये रहा। इन्हीं वर्षों में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति 1996-97 तथा 1997-98 में 587 हजार रही और पाकिस्तान का सैन्य व्यय 1996-97 में 127,441 करोड़ रुपये और 1997-98 में 134.02 करोड़ रुपये रहा है। दोनों देशों की तुलना को गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होगा कि राष्ट्रीय सकल उत्पाद में पाकिस्तान का सैनिक व्यय अधिक है जिसका प्रतिकूल परिणाम वहां की अर्थव्यवस्था पर लगातार बना हुआ है।1 सैन्य शक्ति के बढ़ते प्रभाव का असर पाकिस्तान की राजनैतिक व्यवस्था पर भी है। भारत-पाक संबंधों के विश्लेषण में सैन्य तैयारी और प्रभावों का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है जो इन संबंधों को समझने की जानकारी लगातार देते हैं।

भारत-पाक संबंधों में एक बात का अनुभव लगातार रहता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच मूलभूत अन्तर उसके आकार और क्षमाताओं का है। यह स्थिति 1971 के पश्चात् और भी अधिक स्पष्ट नजर आती है। भारत की जनसंख्या 1994 के मध्य 913 मिलियन थी, पाकिस्तान की जनसंख्या 126.3 मिलियन। भारत का क्षेत्रफल 3288 हजार वर्ग किलोमीटर तथा पाकिस्तान का क्षेत्रफल 796 हजार वर्ग किलोमीटर है। अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी विभिन्नताएं भी पाकिस्तान और भारत के अंतर को लगातार स्पष्ट करती है।

भारत-पाक संबंधों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि अन्य देशों के प्रभावी हस्तक्षेप से पाकिस्तान को बल मिला है। इस क्रम में सबसे पहले उल्लेख अमेरिका का किया जा सकता है। पाकिस्तान आरम्भ से ही अमेरिकी सैन्य संगठन सेन्टो और सिएटो का सदस्य रहा है और इसलिए अमेरिका द्वारा उसे लगातार सैन्य मदद की गई। सैद्धांतिक रूप से यह मदद साम्यवादी प्रभाव को क्षेत्रीय स्तर पर कम करने के लिए प्राप्त होती थी किन्तु इसका व्यावहारिक

उपयोग भारत के विरुद्ध ही हुआ। इन्हीं संबंधों के तहत पाकिस्तान की नीतियों के विभिन्न पक्षों को भी अमेरिकी समर्थन प्राप्त रहा। अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषक 1980 के दशक में अमेरिकी रुझानों में बदलाव देखते हैं और अमेरिका अधिक विवेकपूर्ण और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता है जिसके अन्तर्गत भारतीय पक्ष को आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता रहती है।

चीन का पाकिस्तान को सैन्य और अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नों पर समर्थन-क्षेत्र के बाहर का हस्तक्षेप माना जा सकता है। यह समर्थन 1962 के भारत-चीन संघर्ष के पश्चात् अधिक मुखर और प्रभावशाली हुआ। सैन्य विश्लेषक पाकिस्तान के प्रति चीनी सहयोग को अधिक संतुलक और महत्त्वपूर्ण मानते हैं। चीन ने पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण में ही मदद नहीं दी वरन् उसने अणु शस्त्रों के विस्फोट में पाकिस्तान को पूरा सहयोग दिया। चीन का पिछले कुछ दशकों में विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय विवादों में पाकिस्तान को समर्थन मिला है। चीन का प्रयास दक्षिण एशिया में भारत प्रभाव को सीमित करने की दृष्टि से अधिक रहा है। बाहरी हस्तक्षेप की दृष्टि से पाकिस्तान ने अपने इस्लामी आग्रहों का उपयोग किया है। इसके अन्तर्गत पाकिस्तान को पश्चिम और मध्य एशियाई तेल सम्पन्न राज्यों का सहयोग मिला है। ये राष्ट्र जिसमें सऊदी अरब प्रमुख है, पाकिस्तान के प्रभाव और सम्पन्नता को बढ़ाने में लगातार रुचि लेते हैं और पाकिस्तान में बाह्य दबावों को कम करते हैं।

इस सामान्य पृष्ठभूमि के विश्लेषण के पश्चात् हाल ही में हो रहे विभिन्न प्रयासों का जिनमें पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने और तनावों को कम करने की गंभीर और आवश्यक कोशिश है, उसका आकलन आवश्यक है।

मई, 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण व जून, 1998 में पाकिस्तान द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण में दोनों देशों के बीच के तनावों को काफी बढ़ा दिया था। इस बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परस्पर मिलकर आपस में बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, इसका उन्हें शीघ्र ही अवसर भी मिल गया। जुलाई, 1998 में कोलम्बो में आयोजित दक्षेस का शिखर सम्मेलन जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले एवं चर्चाएं कीं, इस चर्चा का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आपस में वार्ताएं होना निश्चित किया गया। 31 जुलाई, 1998 को दक्षेस सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तारिका अल्ताफ ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा- ''अब बातचीत राजनयिकों के स्तर पर जारी रहेगी।''2 साथ ही यह भी बताया कि डरबन में होने वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की भेंट होगी। इसके अलावा भारतीय विदेश सचिव के. रघुनाथ और पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद के बीच बातचीत के दौर हुए लेकिन इसमें भी कोई प्रगति या समझौता नहीं हो पाया।

लेकिन 18 अक्टूबर, 1998 को भारत-पाकिस्तान की विदेश सचिव स्तरीय बातचीत हुई, जिसे हम अगर सफल या असफल वार्ता न कहते हुए यह कह सकते हैं कि दोनों देशों की बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों पक्षों ने अपनी बातें दोहराई, पर यह अप्रत्याशित ही था क्योंकि दोनों एक-दूसरे से

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

1994 से ही गंभीरतापूर्वक बात नहीं कर रहे हैं। परमाणु परीक्षणों के बाद के हालातों को देखते हुए दोनों ने ही परस्पर विश्वास बनाए रखने की पेशकश कर तर्कसंगत और नियंत्रित दिखने की पूरी कोशिश की।

हालांकि पाकिस्तान के अधिकारियों ने औपचारिक बातचीत के दौरान कोई लचीलापन नहीं दिखाया। इस वार्ता में शामिल विदेश सचिव शमशाद अहमद का मानना है कि, "कश्मीर समस्या आज दुनिया के सबसे जटिल मामलों में से एक है।" पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में यह सबसे बड़ी चुनौती है जिससे वार्ता की मेज पर नहीं निपटा जा सकता है।3

भारत-पाक सम्बन्ध मूलतः विवादों और आपसी विश्वास के अलग-अलग तरीकों के प्रयास करने के बीच ही विकसित होते हुए नजर आते हैं, इन दोनों प्रवृत्तियों को नये राजनयिक वातावरण में देखने का प्रयास रहा है। अगर वार्ता आपसी अविश्वास और तनावों के दौर से गुजरती हुई नजर आती है इसके विपरीत 2004 के बाद के प्रयासों में एक समझ और लचीलापन लगातार नजर आता है। इन प्रवृत्तियों को हम 2005 में सितम्बर तक देखने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें द्विपक्षीय सम्बन्धों की कतिपय घटनाओं को विस्तार से समझने का प्रयास किया गया है, दोनों देशों के बीच आपसी दृष्टिकोणों और समस्याओं को समझने का प्रयास अधिक उल्लेखनीय है न कि परिणाम क्योंकि पारस्परिक विवाद कई अर्थों में परम्परागत रूप में ही उपस्थित है ऐसी स्थितियों में विकसित हो रही पारस्परिक समझ को रेखांकित करना ही इस विश्लेषण का उद्देश्य है।

भारत अपने पड़ोसियों विशेषकर पाकिस्तान से बार-बार दोहरा रहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित में "स्थिर, सुरक्षित और खुशहाल पाकिस्तान" चाहता है। वह लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से गंभीर और निरन्तर बातचीत करना चाहता है। आने वाले समय में भारत-पाक के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग से लेकर सियाचिन तथा सरक्रीक विवादों पर हुए समझौतों पर विचार करने जैसे विषयों पर वार्ता जारी रखने का विचार है। इससे यह तो स्पष्ट है कि उन्हें कश्मीर के प्रश्न का समाधान तो तुरन्त होने की उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में यह विकल्प बचता है कि हम तनावों के क्षेत्रों को कम करते जायें और सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ कर विवादास्पद प्रश्नों से संबंधित दबावों से बढ़े तनावों को कम करने की भूमिका निभा सकने के साथ ही भारत-पाक संबंधों में जो पुरानी कड़वाहट है उसके पक्षों की और उसके अहसास को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि भारत अपने पड़ोसी देश को आश्वस्त करें कि भारत से पाक की भौगोलिक अखण्डता को किसी प्रकार का भय नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही यह बात दोहराता रहता है कि भारत से पाकिस्तान की भौगोलिक अखण्डता प्रभावित हो रही है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद आज तक इसी सोच ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाये रखा है, अगर यह संदेह दूर हो जाता है तो निश्चित ही भारत-पाकिस्तान संबंधों में स्थिरता और शांति स्थापित हो सकती है जो कि इस क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

भारत-पाक सम्बन्ध तथा अमेरिकी समीकरण

वर्तमान परिस्थितियों में भारत को पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी नीति को बहुत ही सोच समझकर और सुनियोजित रूप से निश्चित करना चाहिए। हमें वैश्विक ताकतों के पुन:ध्रुवीकरण, अफगानिस्तान युद्ध के प्रभाव, पाकिस्तान में आन्तरिक परेशानियां, पाकिस्तान के शासकों पर पाक अधिकृत कश्मीर द्वारा लगातार बनाये जा रहे दबाव, पाकिस्तान और भारत की हथियारों संबंधी संभावनाओं के बदलते समीकरणों, विशेषकर दोनों देशों में किये गये परमाणु परीक्षणों के बाद की स्थिति तथा बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

जहां तक परमाणु परीक्षणों की बात की जाती है कि भारत में परमाणु परीक्षणों के साथ ही भारत की स्थिति अधिक मजबूत हो गई है। इस संदर्भ में नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्यसेन का कहना ठीक है कि 1965 के भारत-पाक युद्ध एक पारम्परिक हथियारों के मामले में पाकिस्तान की तुलना में भारत अधिक शक्तिशाली था। उनका आकलन यह स्पष्ट करता है कि भारत में हुए परमाणु परीक्षणों और उसके बाद पाकिस्तान में भी हुए वैसे ही परीक्षणों के बाद भारत और पाकिस्तान की हथियार क्षमता लगभग एकसमान हो गई है। परमाणु हथियारों में विध्वंस की इतनी ज्यादा क्षमता है कि परमाणु युद्ध में किसी का जीतना या हारना कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों परिस्थितियों में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध की बात करना गलत होगा।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रारम्भ में जो कह रहे थे उसमें बदलाव दिखाई देता है क्योंकि यह बदलाव युद्ध के हालात, पाकिस्तान में आंतरिक तनावों एवं गिरते आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक हालातों के कारण हुआ है हालांकि कश्मीर समस्या पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। इसका कारण ज्यादातर पाकिस्तान की अंदरूनी मजबूरियां हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एवं पेंटागन पर 11 सितम्बर, 2001 के हमले के बाद से अमेरिका जिन परिस्थितियों में उलझ गया है, उन्होंने अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसमें पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी शामिल होना पड़ा है। इन परिस्थितियों में दोनों देशों ने आपसी बातचीत एवं विचार-विमर्श द्वारा संघर्ष के मुद्दों को सुलझाने की बात करना शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान द्वारा यह शर्त रखी गयी कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते से पहले कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण हल किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत का स्पष्ट कहना रहा है कि समझौते की बात बिना किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के होना चाहिए। इससे यह अहसास हो रहा है कि युद्ध का माहौल काफी हद तक शांत हो गया। पाकिस्तान के पहले से चले आ रहे कड़े रुख को कम करने में उसकी गिरती आर्थिक स्थिति तथा विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छा महत्त्वपूर्ण रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव एवं संघर्ष को बढ़ाया है। यह आभास हमें 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले में स्पष्ट हो जाता क्योंकि जो हमला हुआ था, उसमें आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

प्रशिक्षित आत्मघाती जिहादी शामिल थे यह बात पाकिस्तान के विभिन्न समाचार पत्रों ने भी स्पष्ट की है।

इसी संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दक्षेस सम्मेलन में जाने से पहले बहुत ही महत्त्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि आतंकवाद का मुख्य स्रोत पाकिस्तान है साथ ही यह कि पाकिस्तान ने अपनी धरती से आतंकवाद फैला रहे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की है, वह संतोषजनक नहीं है इसका पूरा ब्योरा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम यह देखना चाहेंगे कि इसमें 13 दिसम्बर को संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी शामिल है या नहीं। साथ ही पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक मुशर्रफ के साथ मिलना या बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। काठमांडू में आयोजित दक्षेस सम्मेलन में राष्ट्रों के प्रमुखों से पहले जो विदेश मंत्री व विदेश सचिव पहुंचे हैं, उन्होंने शिखर सम्मेलन में उठाए जाने वाले और उठने वाले मसलों की सर्वसम्मति से रेखांकित कर लिया। इसमें प्रमुख मसला 'आतंकवाद' था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकार किया जाए और उस पर अमल किया जाए। विदेश सचिवों के स्तर पर ही इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया था जिसका विरोध पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ नहीं कर पाये वरन् उन्हें आतंकवाद विरोधी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना पड़ा।

जहां तक भारत-पाक विवाद को सुलझाने में महाशक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो उस समय की बात करेंगे जब विश्व की राजनीति का दो महाशक्तियों, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच ध्रुवीकरण था। यह प्रभाव केवल यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया में भी उपस्थित था जिसके दुष्परिणाम भारत और पाकिस्तान ने काफी लम्बे अर्से तक सहे हैं। अमेरिका एवं सोवियत संघ अधिकांशतः अपने-अपने हितों के आधार पर किसी राष्ट्र के मामले में दखलंदाजी करते रहे हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देशों के बीच इन दोनों में से किसी एक महाशक्ति के साथ गठजोड़ के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस स्थिति को नासिर टीटो एवं नेहरू ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से बदलने की कोशिश की। इस आंदोलन के जरिये गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वतंत्र नीतियां अपनाने की गुंजाइश मिल पाई थी। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय दुनिया एक ध्रुवीय रह गयी, क्योंकि अमेरिका अब अकेली महाशक्ति है। 11 सितम्बर के बाद थोपे गये इस वर्तमान आतंकवादी युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पहले जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन विभिन्न शासन प्रणालियों के बीच सद्भाव बनाने का कार्य करता था, वहीं अब इस्लामी एवं गैर इस्लामी देशों को अलग-अलग जमातों में बांटने का प्रयास हो रहा है। ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी राष्ट्र की मध्यस्थता इसे और विवादास्पद बना सकती है।

भारत-पाक सम्बन्धों में बढ़ता तनाव एवं अमेरिकी प्रभाव

11 सितम्बर, 2001 में हुए अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद पहली बार अमेरिका ने भारत-पाक तनाव को गंभीरता से लेते हुए दोनों

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

ही राष्ट्र प्रमुखों को आपसी तनाव कम करने एवं संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका के इस तरह के कूटनीतिक प्रयासों का उद्देश्य शायद यह हो सकता है कि भारत को अपने ऊपर हमले से बचाने के लिए प्रतिरोध की रणनीति अपनाने से रोकना है। अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने इसी तरह का प्रयोग किया था। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर को हुए हमले के बाद यह कहना कि भारत को तुरन्त ही फौजी हमला बोल देना था। भारत की ओर से प्रतिरोध हुआ। आतंकवादियों के खतरे को निर्मूल करने के लिए नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर में स्थित स्थानों पर युद्ध के हालाता वास्तव में मई, 2002 में हुए अल्माटी सम्मेलन से पहले ही बन चुके थे। इस सम्मेलन में वाजपेयी और मुशर्रफ दोनों ही मौजूद थे। वाजपेयी की इस बात से अब अमेरिका सहमत होने लगा कि भारत-पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संवाद तभी रखेगा जब भारत नियंत्रण रेखा से घुसपैठ रूकने को लेकर आश्वस्त हो।

इस संदर्भ में अमेरिका ने मुशर्रफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान स्थायी रूप से घुसपैठ को बंद करे। पाकिस्तान अधीन कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को खत्म करते हुए भारत द्वारा जिन अत्यंत वांछित 20 आतंकवादियों की मांग की गई है उस पर कुछ करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने जब यह बयान दिया कि भारत के साथ पारम्परिक युद्ध की स्थिति में भी पाकिस्तान अणुशक्ति विकल्प अपना सकता है, इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डाला जिसके परिणामस्वरूप पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ ने तुरन्त यह स्पष्ट किया कि वे 'एटमी अविवेक' की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

अमेरिकी प्रयासों से एक सीमा तक युद्ध की संभावनाएं खत्म हो गई लेकिन अब यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि इस उपमहाद्वीप में अमेरिकी प्रभाव महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। जबकि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता रहा है। अमेरिकी प्रभाव अल्माटी सम्मेलन में दिखाई देता है क्योंकि इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने आतंकवाद की भत्र्सना करते हुए अल्माटी करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य देश अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी यह स्पष्ट करते हुए कहा कि, ''मुशर्रफ के भाषण में किए गए आतंकवाद के खिलाफ वादों के अनुरूप वास्तविक कार्यवाहीकिए जाने पर हम अनुकूल कदम उठायेंगे।''

इस तरह अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों का रूस व चीन ने समर्थन किया है लेकिन इससे चीन इस उप महाद्वीप एवं मध्य एशियाई गणराज्यों में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चिंतित भी है। लेकिन भारत फिलहाल तो पाकिस्तान पर दबाव और अमेरिका से निकटता बनाए रखते हुए सीमा पार के आतंकवाद का स्थायी समाधान कराने की कोशिश में दिखाई देता है। उसने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जिसमें 'आतंक की दीवार' का जिक्र करते हुए कहा गया है कि

जिसके एक ओर अफगानिस्तान और दूसरी ओर भारत है तथा पाकिस्तान से जारी घुसपैठ भारत से फैलकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। वाजपेयी ने नियंत्रण रेखा सहित भारत-पाक सीमा की संयुक्त निगरानी के प्रस्ताव के द्वारा भारत के रुख में नरमी का संकेत दिया है।

वैसे यह प्रस्ताव कोई नया नहीं है। 1989 में दोनों देशों के गृह सचिवों ने पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा की प्रभावी और समन्वित निगरानी के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम स्थिति में था और कश्मीर में उग्रवाद शुरू नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान विश्वास बढ़ाने के दूसरे उपायों पर तैयार हो गया लेकिन निगरानी के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि उसने नियंत्रण रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक तैनात करने की मांग की है और संयुक्त निगरानी के प्रस्ताव को भारत के साथ वार्ता की शर्त से जोड़ दिया है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर अमेरिका और ब्रिटिश निगरानी में फौज तैनात करने के इस प्रस्ताव को इन आधारों पर अमान्य कर दिया है कि उस इलाके में यह संभव नहीं और यह भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामले में अन्तरराष्ट्रीय हस्तक्षेप है।

हाल ही में अमेरिका में फिर पाकिस्तान पर प्रतिबन्ध की मांग उठने लगी है, क्योंकि आतंकवाद को मदद देने के लिए नये सबूत सामने आए हैं। यह बात अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता फ्रेंक पलाने ने कही है कि उन्हें इस संदर्भ में जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को पिछले दो माह से बैलेस्टिक मिसाइल के बदले में पाकिस्तान मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाभिकीय अप्रसार ब्यूरो के प्रमुख जान फस बुल्फ उत्तर कोरिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं और आशा है कि वे उसके खिलाफ फिर से प्रतिबन्ध लगाने की अनुशंसा कर सकते हैं।

साथ ही सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचना करते हुए कहा कि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्र के साथ ही अमेरिका के लिए भी खतरा है, बुश प्रशासन को पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी विदेश नीति की समीक्षा करना चाहिए। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे मदरसे मौजूद हैं जहां से इस्लामिक आतंकी संगठनों को शिक्षित किया जाता है। पाकिस्तान की जासूसी संस्था आई.एस.आई. का भी तालिबानों व कश्मीरी आतंकियों से गठजोड़ है। इससे पाकिस्तान में मजबूती प्रदान की जाती है। पलोन ने आगे यह भी कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकी गतिविधियों का केन्द्र बने मदरसे बंद करने का वादा पूरा करने में जनरल मुशर्रफ असफल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों से भागने में छूट नहीं मिलनी चाहिए। अतः पाकिस्तान के व्यवहार को देखते हुए उसके खिलाफ आर्थिक व सैन्य प्रतिबन्ध लगाने का पक्षधर हूं।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद, भारत-पाक सीमा के पार हमले करने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे प्रशिक्षण शिविरों तथा कश्मीर मुद्दे के हल जैसी समस्याओं के बीच सीधी बातचीत करते हुए निपटाने के क्रमबद्ध प्रयास करने चाहिए।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

श्रीनगर-मुज्जफराबाद बस सेवा

भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर बसे हुए कश्मीरियों के लिये 7 अप्रैल, 2005 का दिन अमन के नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। आखिर तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीनगर से मुज्जफराबाद के लिये बस रवाना हो गयी। हालांकि आतंकवादियों ने इसे रोकने के लिए एक दिन पूर्व 6 अप्रैल को श्रीनगर के पर्यटन केन्द्र में आग लगाकर भयभीत करने के पूरे प्रयास किये थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने धैर्य व हिम्मत के साथ अपनी इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इरादे को पूरा किया। साथ ही दोनों ओर के यात्रियों ने सारे खतरों के बावजूद हिम्मत के साथ यात्रा की जिसे वरिष्ठ पत्रकार कमलेश्वर ने इस संदर्भ में कहा कि अगर भयानकतम खतरा उठाकर सफर करने वाले मुसाफिर न होते तो यह अमन का सफरनामा कभी ऐतिहासिक घटना नहीं बन पाता।

श्रीनगर से मुज्जफराबाद तक का 170 किलोमीटर का यह रास्ता वही है जिससे 58 वर्ष पहले पाकिस्तानी कबाइली हमलावर आए थे। यह वही नियंत्रण रेखा है जहां तक भारतीय फौज ने इन पाकिस्तानी हमलावरों को बाहर किया था। आज यह नियंत्रण रेखा शांति रेखा में बदल गई है। शांति की यह प्रक्रिया ऐसी है जिसकी दिशा बदलना बहुत मुश्किल होगा।

जहां तक इस ऐतिहासिक यात्रा की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तानी कश्मीर से 30 यात्रियों में से पाँच महिलाएं थीं। भारत की ओर से उनका स्वागत अमन सेतु पर किया गया। यह वही पुल था जो 58 साल पहले हमलावरों ने तोड़ दिया है। जो भारत-पाक नियंत्रण रेखा का विभाजक प्रतीक बना था और इसे पुनः जोड़ा गया है। मुज्जफराबाद के इस काफिले को वहां के प्रधानमंत्री सिकन्दर हयात ने रवाना किया। भारत से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर विदेश मंत्री नटवरसिंह एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थीं।

लेकिन इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ कहीं भी दिखाई नहीं दिए जबकि उनकी स्पष्ट सहमति के बिना शांति यात्रा सम्भव ही नहीं थी। यही बात मुशर्रफ की राजनीतिक और राजनयिक सूबबूझ का गहरा परिचय देती है। पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी ने इस शांति यात्रा का गहरा विरोध किया था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तो शुरू से ही इस सड़क को खोले जाने का विरोध कर रहे थे। भारतीय कश्मीर में भी चार आतंकवादी जमाते और हुर्रियत कान्फ्रेंस इस शांति यात्रा के विरोध में थी। उन्होंने कश्मीर बंद की घोषणा कर रखी थी। साथ ही यह बात भी सही है कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारत विरोधी आतंकवादी संगठन अभी भी सक्रिय हैं यह भी प्रमाणित होता है कि यह सब उस समय प्रारम्भ हुआ था जब पाकिस्तान में फौजी शासक जिया-उल-हक थे। तभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने रूसी आधिपत्य का विरोध शुरू किया था और पाकिस्तान को भरपूर फौजी और आर्थिक सहायता दी थी। उसी मदद से जिया-उल-हक ने अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया था और भारत के विरोध में आतंकी जिहादियों को। इसलिए कश्मीर में आतंकवादियों का संचालन

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई करती थी। यह सब पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समय तक चलता रहा है।

यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि इन भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान सरकार की मदद प्राप्त नहीं है, यह देखना बेहद आवश्यक हो गया कि इन खतरनाक संगठनों के पीछे कौन है ? आखिर कोई एक या कई शक्तियां ऐसी तो अवश्य हैं जो पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी मौजूद हैं जो भारत-पाक शांति प्रयासों को विफल बनाना चाहती है, नहीं तो श्रीनगर के पर्यटक केन्द्र को इतनी बुरी तरह जलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह तो अच्छा हुआ कि श्रीनगर से मुज्जफराबाद जाने वाले 21 यात्री इसी टूरिस्ट सेन्टर के परिसर में सुरक्षा के लिए रखे गए थे। वे भाग्य से सामने वाली दूसरी इमारत में थे, इसीलिए बच गये। दोनों तरफ की जनता शान्ति चाहती है और उनके इन सद्प्रयासों से ही शांति आई, दोस्ती की नई राह खोली है। इस रास्ते का विस्तार करने के लिए जनता के बीच सम्पर्कों को और अधिक बढ़ाया जाए। उम्मीद यही है कि कारगिल स्कार्टू का रास्ता तो खुलेगा ही, बहुत जल्दी राजस्थान के साथ जम्मू-सियालकोट का रास्ता भी खुल सकेगा। दोनों देशों के बीच सम्पर्क के ये प्रयास नये सम्बन्धों की शुरुआत है।

पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा 16 से 18 अप्रैल, 2005

पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तीन दिन की भारत यात्रा (16 से 18 अप्रैल, 2005) इस बार बहुत ही सहजता के साथ सम्पन्न हो गई। इस बार पूरी यात्रा के दौरान ऐसा एक शब्द नहीं कहा जिससे मेजबान भारत को तकलीफ हों उन्होंने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अमन की दुआ की। नई दिल्ली में भारत-पाक वन-डे मैच देखा। पूरी तरह तनावमुक्त और खुश दिखाई दिए। यहां तक कि यात्रा के अंतिम दिन साझा बयान जारी करने की खातिर उन्होंने फिलीपीन्स के लिए अपनी उड़ान दो घण्टे टाल दी। पत्रकार वार्ता में निःसंकोच प्रश्नों के जवाब देते दिखाई दिए और कहा कि, ''मैं नया दिल लाया हूँ।''

यह सब सुखद रहा क्योंकि पिछली यात्रा 2001 में आगरा शिखर वार्ता के दौरान वे काफी उत्तेजित रहे, पत्रकार वार्ता में जवाब नहीं दिए और साझा बयान की बैठकर छोड़कर चले गये लेकिन इस बार मित्रता, भाई-चारे और सद्भाव के रूप में दिखाई दे रहे थे। इस संदर्भ में स्वयं मुशर्रफ ने कहा भी है कि ''उस समय हम एक-दूसरे से नाराज थे। एक-दूसरे की हत्या कर रहे थे। चौतरफा तनाव था। अब दोस्ती है और माहौल खुशनुमा है।''

दोनों देशों के प्रमुखों मनमोहन सिंह एवं मुशर्रफ के बीच बातचीत में कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सीमाओं का निर्धारण संभव नहीं है, लेकिन वे दोनों देशों की जनता को नजदीक लाना चाहते हैं। दोनों देशों ने संयुक्त व्यापार परिषद् गठित करने का एवं राजस्थान के मुनाबाव और सिंध के खोखरापार के बीच अक्टूबर के बजाय दिसम्बर तक रेल सम्पर्क बहाल करने पर सहमति जताई। साथ ही भारत-पाक ने व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार परिषद् गठित करने व बगलीदार बांध विवाद निबटारे के लिए तटस्थ एजेन्सी को सौंपे जाने

पर सहमत हो गए। दोनों देश श्रीनगर-मुज्जफराबाद बस सेवा के फैरे बढ़ाने, सियाचिन और सरक्रीक मुद्दे के समाधान पर भी सहमत हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और इस दौरान आने वाली समस्याओं कानिश्चित रूप से समाधान चाहेंगे।

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच 17 अप्रैल को महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई। दोनों शीर्षस्थ नेताओं के बीच बातचीत लगभग तीन घंटे तक चली। इसके पहले दोनों ने शिष्ट मण्डल स्तर की वार्ता की। फिर दोनों ने विदेश मंत्रियों के साथ और अंत में अकेले चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में विदेश मंत्री नटवर सिंह, रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, विदेश सचिव श्याम सरन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी. के. नायर, पाकिस्तान में भारत के राजदूत शिवशंकर मेनन और विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान सम्बन्धी मामलों के संयुक्त सचिव दिलीप सिन्हा शामिल थे। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मण्डल में मुशर्रफ के साथ वहां के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, सूचनामंत्री राशिद शेख और व्यापार एवं वाणिज्य के वरिष्ठ अधिकारी थे।

इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अपने पक्ष को रखते हुए शिकायत की थी सर्वाधिक प्राथमिकता वाले देश (एमएफएन) का दर्जा दिए जाने का कोई लाभ नहीं हुआ है। भारतीय शुल्क और गैर बाधाएं व्यापार सम्पर्कों को बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान करने का भारत द्वारा आश्वासन देकर सहमति जताई गई।

साथ ही फरवरी में विदेश मंत्री नटवरसिंह की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी थी उन्हीं को फिर से आगे बढ़ाने की बात हुई। मुनाबाव-खोखरापार रेल लाईन के खुलने की तिथि 2 अक्टूबर से बढ़कर दिसम्बर, 2005 हो गई और कराची और मुम्बई में वाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय के प्रति दोनों देशों में प्रतिबद्धता दिखाई।

भारत-पाक विदेश मंत्री स्तर वार्ता 5-6 सितम्बर, 2004: दिल्ली

भारत के विदेश मंत्री नटवर सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद के बीच वार्ता के बाद नई दिल्ली में जारी संयुक्त बयान में इस बात पर विश्वास प्रकट किया गया कि दोनों देशों के बीच जारी समग्र संवाद के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय समस्याओं का शांतिपूर्ण व दोनों पक्षों में स्वीकार्य समाधान हो जायेगा।

दोनों विदेश मंत्रियों में समग्र बातचीत की प्रक्रिया को गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों व चार्टर पर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए दोनों ने शिमला समझौते की भावना को पूरी तरह लागू करने की इच्छा व्यक्त की। 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त बयान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आतंकवाद और हिंसा से मुक्त वातावरण में बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा।

संयुक्त बयान के अनुसार 13 मुद्दों पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सहमति हुई। पारम्परिक व परमाणु मामलों में आपसी विश्वास

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दोनों देशों के विशेषज्ञों की बैठक होगी। इस बैठक में मिसाइल परीक्षण के बारे में अग्रिम चेतावनी के सम्बन्ध में तैयार किए गए समझौते के मुद्दों पर विचार होगा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेन्जर्स के बीच वर्ष में दो बार बैठक होगी। दोनों देशों के नारकोटिक्स नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें आशय पत्र को अंतिम रूप दिया जायेगा। नवम्बर में भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मेरी सिक्यूरिटी एजेन्सी के बीच बैठक होगी, जिसमें संचार सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में आशय-पत्र पर विचार होगा। व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जायेगी। सियाचीन के सम्बन्ध में रक्षा सचिवों की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया जायेगा। सरक्रीक क्षेत्र में सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वे कराया जाएगा। नागरिक कैदियों व मछुआरों के सवाल को प्रभावी व तेजी के साथ निपटाने के लिए कोई तंत्र विकसित किया जायेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जायेगी। ऐतिहासिक स्थलों के रख-रखाव के सम्बन्ध में भी कदम उठाए जायेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच विचार-विनिमय को बढ़ावा दिया जायेगा, और विदेश सेवा के प्रशिक्षु अध्ययन के लिए एक-दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उच्चस्तरीय मुलाकातों व यात्राओं को बनाए रखा जाए। यह भी निश्चित हुआ कि दिसम्बर, 2004 में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होगी, जिसमें शांति, सुरक्षा और जम्मू व कश्मीर के अलावा अन्य मुद्दों पर बातचीत की समीक्षा की जायेगी। अंत में संवाददाता सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान ने उम्मीद जताई कि मुम्बई व कराची में वाणिज्य दूतावास खोलने के फैसले को जल्द ही कार्यरूप दे दिया जाएगा जिससे दोनों देशों की जनता को वीजा लेने में सुविधा हो सकेगी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ दो दिवसीय वार्ता के अंत में भारत के विदेश मंत्री के. नटवर सिंह का कहना था कि, ''बातचीत में थोड़ी बहुत तरक्की भी बड़ी बात है हमने आपस में घनिष्ठता बनाई है और आपसी विश्वास कायम किया है।''4 साथ ही कहा कि मौजूदा स्थितियों में यह एक बड़ी कामयाबी है तथा शांति के रास्ते पर एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक बड़ी मेहनत से प्राप्त किया जा रहा है।5

दोनों विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बहुत ही सावधानी बरती। भारतीय विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा कि सीमा पर से घुसपैठ चिंता का विषय बना हुआ है और हमने अपनी चिंता से कसूरी को वाकिफ करा दिया है।''6 कसूरी ने कुछ इसी तरह जवाब दिया कि, ''हमारा सुझाव था कि हम कुछ ही शब्द इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम सभी दोनों मुल्कों के बीच तनाव की वजह जानते हैं- जो कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र में रखने के कारण है।7 इसका अर्थ यह हुआ कि परम्परागत मुद्दा बरकरार था, लेकिन कसूरी की ओर से बातचीत को 'सौजन्यतापूर्ण' बताया जाना इस बात का सबूत था कि किसी को निकट भविष्य में इस मसले के हल होने की उम्मीद नहीं है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

पाकिस्तान ने इस बात पर अपने रुख को लचीला बनाते हुए घोषणा की कि वे मुम्बई में जिन्ना हाऊस को पाकिस्तान का वाणिज्य दूतावास बनाने की मांग छोड़ने को तैयार है तथा अब आगे कदम बढ़ाने की बारी भारत की है।

श्रीनगर से पाकिस्तान के अधीनस्थ मुज्जफराबाद तक बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव राजनैतिक प्रतीकवाद में उलझ सकता है। लेकिन खोखरापार-मुनाबाव रेलमार्ग पर कुछ प्रगति मुमकिन है। दोनों ही देश पर्यटकों के लिए सामूहिक वीजा देना शुरू करेंगे और पत्रकारों के लिए यात्रा को आसान बनाएंगे। इसके अलावा भारत के सिख तीर्थ यात्री भी पाकिस्तान में ननकाना साहब जा सकेंगे।

लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रगति ऊर्जा के क्षेत्र में हुई है। इस संदर्भ में कसूरी ने कहा कि, "हमारे पेट्रोलियम और गैर मंत्रालय के अधिकारी सभी तरह के मामलों पर बातचीत के लिए इस वर्ष बैठक करेंगे। मेरे मित्र मणिशंकर अय्यर (भारतीय पेट्रोलियम मंत्री) ने डीजल निर्यात को हरी झंडी दे दी है।"8

पाकिस्तान हर साल कुवैत और मध्य-पूर्व के दूसरे देशों से 45 लाख टन डीजल का आयात करता है। इस पर भारत ने सुझाव दिया है कि वह जालंधर से लाहौर तक पाइपलाइन बिछाकर पाकिस्तान की समस्त जरूरतें पूरी कर सकता है। इससे ईरान के असुलिएह से पाकिस्तान के रास्ते गुजरात में तेल पाइप लाइन बिछाने पर भारत आसानी से तैयार हो सकता है। लगभग एक दशक से यह सौदा रूका हुआ है। भारत को भय है कि पाकिस्तान इस पाइप लाइन के कारण उसकी ऊर्जा सम्बन्धी नीति को अपने नियंत्रण में कर सकता है।

कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि मुख्य रूप से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे. एन. दीक्षित और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के विशेष सलाहकार तारिक अजीज के बीच अनौपचारिक वार्ताओं को उसी तरह अधिकारिक स्वरूप प्रदान किया जाए जैसा कि भारत-चीन वार्ता के सम्बन्ध में हुआ है। भारत बार-बार चीन-भारत वार्ता का प्रतिमान पाकिस्तान को सुझाता रहा है। उसका सुझाव रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर पर पूर्वाग्रह के बिना सभी मुद्दों पर बातचीत की इजाजत दे। पाकिस्तान के इस सुझाव पर भारत की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि भारत शायद इस पर राजी नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि "दीक्षित और अजीज की बातचीत दरअसल इसलिए सफल रही है क्योंकि उसे अधिकारिक दर्जा हासिल नहीं है। लेकिन उसे अधिकारिक रूप देने से मकसद हल नहीं होगा।"9

इस तरह बातचीत में प्रगति का मजबूत संकेत तो समझौते वाले क्षेत्रों में नहीं नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी वार्ताओं का दौर चलता है उनके साथ दोनों देशों की जनता की बहुत अधिक उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लेकिन अब सीमाओं के दोनों और लोगों को लगने लगा है कि भावनाओं के दिन अब नहीं रहे हैं। अगर भारत-पाक वार्ता समाचार पत्रों में अब मुख्य समाचार नहीं बनती है तो यह शायद अच्छा संकेत है।

अब तो लगता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री कोलीन पावेल ने भी वास्तविक स्थिति को समझ लिया है। इसलिए नटवर सिंह एवं कसूरी की

बातचीत पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा है "कश्मीर बहुत ही जटिल मुद्दा है।" अन्ततः यही कहेंगे कि इस वार्ता से इतना तो सुनिश्चित हो गया है कि कम से कम अगले वर्ष के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी।

भारतीय विदेश मंत्री नटवरसिंह की पाक यात्रा: अक्टूबर, 2005

अक्टूबर, 2005 में भारतीय विदेश मंत्री नटवरसिंह एवं पाक विदेश मंत्री खुर्शीद मोहम्मद कसूरी के बीच एक बार फिर वार्ता हुई जिसमें ईरान-पाक-भारत पाइप लाइन की बात को स्पष्ट तौर पर दोहराते हुए आपसी संबंधों के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने मूलभूत बातों पर एक-दूसरे को हमेशा की तरह आश्वस्त किया है अर्थात् भारत ने कहा है कि वह कश्मीर का संतोषजनक हल निकालना चाहता है और पाकिस्तान ने कहा है कि वह आतंकवाद को मूल से खत्म करने के लिए अडिग है। तात्पर्य यह कि दोनों देशों में इन दोनों समस्याओं का जिक्र किया व इसे अलग रखते हुए अपनी मजबूरियों का अहसास करवाते हुए यह चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ सकते उन्हें अपनी जगह रहने दें और जिन पर बढ़ सकते हैं, उन पर बढ़ जाएं, यही एक सफल कूटनीति है। इसी आधार पर भारत और पाकिस्तान ने इस बार कई महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं। इन समझौते से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जनता के दबाव की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। दोनों देश वीजा में ढील देने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी वीजा मिलना उतना कठिन है, जितना कि कभी रूस और अमेरिका के बीच हुआ करता था। दोनों देशों को संभ्रात नागरिकों पर भी शक बना रहता है कि कहीं वे जासूसी तो नहीं करेंगे। भारत में तीर्थयात्रियों के लिए विशेष छूट देने का आग्रह किया है। इसी प्रकार उसने एक ही वीजा में कई यात्राएं करने की अनुमति का सुझाव भी दिया है। जैसे दोनों कश्मीरों के बीच आजकल बसें चल रही हैं, वैसे ही दोनों पंजाबों (अमृतसर-ननकाना साहब) के बीच चलाने का भी सुझाव है। रावलकोट और पुंछ के बीच भी बस चले और कश्मीरों के बीच ट्रक चलने लगे तो भारतीय माल पाकिस्तान और अफगानिस्तान होता हुआ ईरान और तुर्की तक पहुंच सकता है। सरक्रीक के संयुक्त सर्वेक्षण पर सहमति हुई और बगलीघर पर मध्यस्थता की प्रक्रिया चल ही रही है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को थोड़ा बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है।

यह ठीक है कि सियाचीन के मामले में मतभेद अब भी बने हुए हैं। पाकिस्तान सियाचीन के सीमांकन के बिल्कुल विरुद्ध है। उसका मानना है कि भारत ने उसे गफलत में रखा और वार्ता के दौरान ही सियाचीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यदि अभी सीमांकन हुआ तो भारतीय अधीनस्थ को वैधता मिल जाएगी। इधर भारत का यह मानना है कि यदि सियाचीन का हिमखंड हमने खाली कर दिया तो कहीं पाकिस्तान उसके अनेक सामरिक ठिकानों को अपने कब्जे में न कर लें। इन पारस्परिक शंकाओं के बावजूद दोनों पक्षों ने सियाचीन का मसला हल करने के लिए इस बार कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई है। विस्तार से बातचीत की है। शीघ्र ही दुबारा बात करेंगे। यह रवैया रचनात्मक और आशाजनक है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रक्षेपास्त्रों के बारे में जो महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ वह कैसे होता ? दोनों

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

पक्षों ने यह समझौता किया है कि वे अपने-अपने प्रक्षेपास्त्र परीक्षण स्थल सीमा से कम से कम 40 कि.मी. दूर रखेंगे ताकि जब भी कोई परीक्षण किया जाए तो पड़ौसी देश में तनाव नहीं फैले। प्रयत्न यह होगा कि परीक्षण का प्रभाव सीमा से 75 किमी. क्षेत्र के बाहर ही हो। इसके अलावा दोनों राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच ऐसी होटलाइन की स्थापना का भी निर्णय हुआ है, जिसकी मदद में सामुद्रिक मछुआरों को तुरन्त सहायता मिले। एक-दूसरे की जल सीमा में गलती से चले जाने पर अब गिरफ्तारी का अंदेशा चला जाएगा। दोनों ओर के अधिकारी अब सामुद्रिक प्रदूषण, सामुद्रिक अपराध निवारण और सामुद्रिक विपदा के मौकों पर आपस में सहयोग करेंगे। पारस्परिक सहयोग को नियमित और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने जो सबसे उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है वह है संयुक्त आयोग को सक्रिय करना। जो कि पिछले 16 वर्षों से बंद पड़ा था। यह आयोग अब खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार आदि अनेक क्षेत्रों में बंद दरवाजों को खोल देगा। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विदेश मंत्री नटवरसिंह की इस पाकिस्तान यात्रा ने इधर उभरे निराशा के वातावरण को दूर किया है और बहुत अधिक मुखर हुए बिना पारस्परिक संबंधों को शांति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ वार्ता

संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अमेरिका के न्यूयार्क पैलेस में परस्पर चर्चा की यह चर्चा लगभग चार घंटे तक चली इसके पश्चात् एक बयान जारी किया गया जिसे पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ ने पढ़ा। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में शांतिपूर्ण बातचीत से समाधान के संभावित विकल्पों के लिए पूरी तरह गंभीरता और उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।'

वैसे दोनों पक्ष अपने पुराने रुख पर ही कायम रहे। भारत ने सीमा पार के आतंकवाद को मुद्दा बनाए रखा तो मुशर्रफ ने कश्मीर की बात पर ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विवादास्पद कश्मीर प्रस्ताव का जिक्र किया। इससे पहले भी वे कह चुके थे कि हम अतीत के मसलों की अनदेखी नहीं कर सकते। फिलस्तीन के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी शांति और न्याय मिलना चाहिए।

इसके एकदिन पूर्व भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति बुश के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि पाकिस्तान से 'आतंकवाद का प्रवाह' नहीं थमा है। भारत कश्मीर मुद्दे पर बातचीत से पहले आतंकवाद थमने के पुख्ता सबूत के पक्ष में है तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल घाटी में भारतीय फौजों की तैनाती में कमी की घोषणा भारत द्वारा चाहता था। लेकिन मुशर्रफ ने सुरक्षा परिषद् के पुराने प्रस्ताव का मसला उठाकर-जो पाकिस्तानी लोगों के लिए लक्षित था-स्पष्ट कर दिया कि दोनों पक्षों में गतिरोध आ गया है और वे न्यूयार्क में कोई महत्त्वपूर्ण घोषणा न करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यह बैठक काफी अच्छे वातावरण में सम्पन्न हुई।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों ने अपने आपसी सम्बन्धों को सामान्य करने के लिये जहाँ एक ओर परस्पर प्रयास किये वहीं उन्होंने तनावों को दूर कर आपसी सहयोग को विकसित करने की चेष्टा की। इन प्रयासों में वे प्रयास अधिक उपयोगी हैं जो दोनों देशों के नागरिकों की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। आपसी बढ़ते हुए सम्पर्कों को दोनों देशों के नेतृत्व ने आवश्यक माना। यही नहीं क्षेत्रीय आवश्यकताओं ने भी दोनों देशों के सम्बन्धों को प्रभावित किया है। भारत-पाक सम्बन्धों में जब सामान्य के साथ बढ़ते हुए सम्बन्ध नये आधारों को जन्म दे सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1.एशियन स्ट्रेटेजितक रिव्यू, 1996-97, इन्स्टीट्यूट फार डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालीसिस, पृष्ठ 51 और 61

2.इण्डिया टुडे, 4 नवम्बर, 1998

3.हिन्दुस्तान टाइम्स, 19 अक्टूबर, 1998

4.श्रीनगर-मुज्जफराबाद बस सेवा (लेख), दैनिक भास्कर, अप्रैल, 2005

5.पुष्पेश पंत, 'भारत-पाक संबंध' (लेख), दैनिक भास्कर, 19 अप्रैल, 2005

6.इन्द्राणी बागची, 'भारत-पाकिस्तान वार्ता' (लेख), इण्डिया टुडे, 20 सितम्बर, 2004, पृष्ठ 12

7.वही

8.वही

9.वही